Reserved

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD
BENCH ALLAHABAD
*****

(THIS THE 21st DAY OF April, 2011)

Hon'ble Dr.K.B.S. Rajan, Member (J)
Hon'ble Mr. D.C.Lakha, Member (A)

Original Application No.1044 of 2007
(U/s 19, Administrative Tribunal Act, 1985)

Umesh Chandra Pandey, S/o Sri Awadh Narain Pandey, R/o 117/203, M-Block, Kakadeo, Kanpur Nagar.

.... *Applicant*

Present for Applicant :*Shri O.P.Gupta*, Advocate.

Versus

1. Union of India, through Secretary, Ministry of Communication, Govt. of India, New Delhi.
2. Sr. Superintendent of Post Offices, City Division, Kanpur 01.
3. Director Postal Services Agra, office of PMG Kanpur Region, Kanpur.

.... *Respondents*

Present for Respondents : *Shri R. K. Srivastav, Advocate*
Shri R.D.Tiwari, Advocate.

ORDER

(Delivered by Hon. Dr. K. B. S. Rajan, Member-J)

A peculiar case. When an employee is dismissed from service and later on reinstated, and during the period he was out of service he had been arrested under some criminal proceedings, is he under any legal obligation to inform the administration about the fact of his having been arrested and kept in custody for a substantial period.

The inquiry officer has, after holding the inquiry held that there is no violation of the rules, while the disciplinary authority held otherwise and the appellate authority endorsed the decision of the disciplinary authority. In addition, there are certain other charges, which the disciplinary authority, disagreeing from the finding of the inquiry officer, had held as proved and punishment of reduction to a lower stage for two years with cumulative effect.

2. Brief facts: The applicant was earlier in service and was proceeded against under Rule 14 of the CCS (CC&A) Rules, 1965 and was dismissed on 26-07-2000 and later on by the order of the Revisional Authority, he was permitted to resume duties on 13-02-2002. During the inter-regnum period, he remained jail for the period from 28-04-2001 to 11-07-2001. This fact was not informed to the authorities by the applicant on his resuming the duties or immediately thereafter, though on 01-01-2003 communication of the above fact was given by the applicant. The applicant was issued with a charge sheet containing the following charges:-

> *अनुच्छेद – 1 यह कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय पोस्टमैन नवीन नगर (निलंबित) ने दिनांक 13–02–02 को कार्य भार ग्रहण करने के समय व उसके बाद दिनांक 01–01–03 तक दिनांक 28–4–01 से 11.07.01 तक अन्तर्गत मुकदमा संख्या–134/2000 थाना काकादेव द्वारा गिरफतार करके जेल में बंद रहने की सूचना न देकर एम एच ओ ओ एम सं0 30/59/54–ई एस टी टी (ए) दिनांक 25–02–55 के तहत वर्णित आदेशो का पालन नहीं किया । अतः आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय ने उक्त वर्णित आदेश का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उक्त पद पर कार्य करते हुए उक्त ज्ञापन में वर्णित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । इसके साथ ही साथ सी0 सी0 एस0 (कन्डक्ट) नियमावली 1964 के नियम – 3 के नीचे भारत*

सरकार के निर्णय सं0 – 5 जो जी आई एम ए एच ओ एम सं0 41/2/55 (II) ई एस टी एस ए दिनांक 23–4–55 का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

<u>अनुच्छेद – II</u> - यह कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय पोस्टमैन नवीन नगर (निलंबित) ने दिनांक 13–02–02 से 04–04–2003 तक उक्त पद पर कार्य करते हुए तत्कालीन पी आर आई (पी) एच एन एस डाकघर श्री नथमल राठी द्वारा उनके विरूद्ध आज अखबार की कटिंग दिनांक 02–05–01 की जांच में तथ्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए छिपाते हुए भ्रामक बयान देकर सरकारी जांच में बाधा डाली एवं विभाग को गुमराह किया । अतः आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय ने उक्त पद पर कार्य करते हुए वांछित सत्यनिष्ठा का पालन न करते हुए सी0 सी0 एस0 (कन्डक्ट) नियमावली 1964 के नियम – 3 – 1 (i) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

<u>अनुच्छेद – III</u> - यह कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय पोस्टमैन नवीन नगर (निलंबित) ने श्रीमती सुनीता गौतम पुत्री श्री दुलीचन्द निवासिनी – 163 ई डब्ल्यू एस वर्रा – 5 जनता नगर, कनपुर की शिकायत दिनांक 05–06–02 की जांच सहायक अधीक्षक पश्चिम (तत्कालीन) श्री सी वी शर्मा द्वारा जांच के दौरान जेल में रहने की अवधि की सूचना अपने बयान दिनांक 10–02–02 में व्यक्तिगत लाभ के लिए छिपाया । तदनुसार आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय ने उक्त अवधि में उक्त पर कार्य करते हुए सी0 सी0 एस0 (कन्डक्ट) नियमावली – 1964 के नियम – 3 – 1 (ii) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

<u>अनुच्छेद – IV</u> – यह कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय पोस्टमैन नवीन नगर (निलंबित) ने दिनांक 13–02–02 से 04–04–2003 तक उक्त पद पर कार्य करते हुए एक ऐसा आचरण व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रस्तुत किया जो किसी सरकारी कर्मचारी से अपेक्षित नहीं था । अतः आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री उमेश चन्द पाण्डेय ने उक्त अवधि में कार्य करते हुए सी0 सी0 एस0 (आचरण) नियमावली 1964 के नियम – 3 – 1 (iii) स्पष्ट उल्लंघन किया है।"

3. The inquiry authority has held the charges 1, 2 and 4 as not proved while charge No. 3 stood proved. His findings are as under:-

"श्री उमेश चन्द पाण्डेय पोस्टमैन नवीन नगर, आरोपित कर्मचारी के लिखित सार दि0 29–03–2005 में तर्क दिया गया कि जेल होने के दौरान वह

ड्यूटी पर नहीं था तथा नौकरी के किसी पद पर तैनात नहीं था । सर्विस से डिसमिसिल होने के बाद उसे अरेस्ट किया था तथा जेल में रहा था । अतः जब जेल में रहने के दौरान वह विभागीय सरकारी सर्विस में था ही नही तो विभागीय उच्च अधिकारी को सूचना भेजने का कारण ही नही बनता यदि वह सर्विस में होता तो सूचना भेजनी आवश्यक थी ।

इस प्रकार आरोपित कर्मचारी श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय ने जेल में रहने की अपील 28-4-01 से 11-7-01 की सूचना स्वयं डिसमिसल फ्राम सर्विस पीरियड के दौरान नहीं भेजी तथा पुनः ड्यूटी ज्वाइन की तिथि दि0 13-2-02 को व उसके तुरन्त बाद नहीं भेजी जब दिनांक 10-7-02 को उसका लिखित बयान (S-3) लिया गया तो उसमे उसने जेल जाने की बात बताई अतः अनुच्छेद – 1 सिद्ध नहीं होता क्योंकि आरोपित कर्मचारी जेल में रहने के दौरान नौकरी में नहीं था ।"

"आरोप सं0 – II

श्री नथमल राठी (SW-05) ने अपने बयान दि0 13-10-04 की जांच के दौरान दिए कि उसने श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय बयान दि0 28-03-02 (S-06) S-05 को दिखाकर लिया था जिसकी रिपोर्ट S-07 द्वारा उसने प्रेषित की थी । आरोपित कर्मचारी ने S-06 में लिखा कि आज समाचार पत्र दि0 02-05-2001 की कटिंग में दर्ज उसके विरूद्ध आरोप से उसका कोई संबंध नहीं है । तथा उसके खिलाफ संबंधित मामला में किसी भी थाना में वह बंद नहीं हुआ । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अपने स्तर में इस मामला को S-01 व SW-2 से सम्मिलित कर आरोप की पुष्टि की है परन्तु आरोपित कर्मचारी ने अपने सार में पेपर कटिंग मामला से सम्बन्धित केश उसके विरूद्ध ना होने की बात लिखी है । आरोप के समर्थन में अन्य मुख्य गवाह वह उनके सम्बन्धित अभिलेख जांच में उपस्थित नहीं हुए । अतः आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध यह आरोप सिद्ध नहीं होता है ।"

4. The disciplinary authority had disagreed from the above findings stating as under:-

"आरोप सं0 – 1 -

आरोप के अनुसार कर्मचारी ने दुबारा विभागीय सेवा मे आते समय दिनांक 13-02-02 को पिछले साल जेल मे रहने एवं उससे सम्बन्धित चल रहे न्यायालय के अपराधिक मामले के तथ्यों को छिपाया । जांच अधिकारी ने आपराधिक तथ्यों को पुष्ट पाया किन्तु जेल जाने की अवधि कर्मचारी के सेवा से बाहर रहे होने के समय से सम्बद्ध होने के कारण आरोप को सिद्ध न होना बताया । जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष पर असहमति की टिप्पणी दी गयी थी । अपने प्रतिवेदन में कर्मचारी ने उन्हीं तर्को का सहारा लिया है । और कहा है कि जेल जाने के समय

उसके सूत्र सम्बन्ध विभाग को साथ नहीं थें अतः सूचना न देने का आरोप अर्थहीन है बाद में विभाग में आने के बाद जब पूछा गया तब वस्तुस्थिति बतायी गयी ।

यह सत्य है कि जेल जाने की अवधि में कर्मचारी विभागीय सेवा से बाहर था परन्तु जेल जाना तथा उससे संबंधित चारित्रक – पतन का गम्भीर मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होना तथा कर्मचारी का जमानत पर होना दुबारा विभागीय सेवा में भार ग्रहण करते समय सेवा के लिए आपेक्षित आवश्यक योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते है अतः कर्मचारी के लिये नियमानुसार आवश्यक था कि वह विभाग में दुबारा भार ग्रहण करने की दशा में आपराधिक तथ्यों को सूचित करता जो कि उसने नहीं किया । अतः आरोप सिद्ध होता है ।

आरोप सं0 – 2 -

जांच अधिकारी ने इस आरोप को सिद्ध नही पाया है कि कर्मचारी ने आज अखबार में दिनांक 02–05–01 को छिपी सुनीता गौतम से सम्बधित समाचार को अपने से असम्बध्द बताया था । इस निष्कर्ष पर भी असहमति व्यक्त की गयी थी । कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि समाचार पत्र का सम्बन्धित प्रकरण सुनीता व बलवान सिंह का व्यक्तिगत मामला था तथा आरोपित कर्मचारी का प्रकरण के आपराधिक मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

यह सही है कि प्रकरण के आपराधिक तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है किंतु कर्मवारी द्वारा प्रस्तुत गवाह भी श्री बलवान सिंह ने प्रकरण से सम्बद्धता की पुष्टि की है तथा अखबार में छपे विवरण में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय का भी नाम है जबकि कर्मचारी ने प्रकरण से पूरी असम्बद्धता बतायी थी अतः आरोप को असिद्ध नहीं माना जा सकता है । अतः पूर्णतः सिद्ध है ।"

5. The disciplinary authority has, vide order dated 23-11-2005, imposed penalty as under:-

"उक्त विवेचन से यह पूर्णतः सिद्ध है कि आरोपित कर्मचारी पर लगाए गए आरोप पूर्णतः सिद्ध है तथा कर्मचारह एक लोक सेवक के अनुरूप आचरण बनाए रखने में पूर्णतः असफल रहा । तदनुसार में के0 के0 यादव प्रवर अधीक्षक डाकघर कानपुर नगर मण्डल कानपुर कर्मचारी श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय के वेतन, रूपया 3050–75–3960–80–4590 के वेतनमान में रूपया 3575/. से तीन स्तर नीचे रूपया 3350/– पर दो वर्ष के लिए तात्कालिक प्रभाव से घटाए जाने का दण्ड अनुमान्य करता हूँ और तदनुसार आदेश पारित करता हूँ । यह वेतन घटाए जाने का आदेश उक्त अवधि के बाद भविष्य की वेतन वृद्धियों के स्थगन पर प्रभाव डालेगा । और कर्मचारी इस दो वर्ष की दण्ड अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा ।"

6. The following are the grounds of appeal before the appellate authority:

> ***"1-*** ***In the penalty order against charge no. 4 proceeding to the operative portion, it has been observed by the disciplinary authority as under:***
> ****(Hindi)***
>
> ***But in the last para of order of punishment it has been mentioned as under:***
> ****(Hindi)***
>
> ***This leads the conclusion drawn by the disciplinary authority is vague***
>
> ***2-*** ***The penalty order is also unreasoned and not speaking."***

7. The Appellate authority has, vide order dated 29-06-2007 rejected the appeal stating that the plea put forth by the appellant is baseless and not considerable and holding that he did not find any ground to intervene into the decision of the disciplinary authority rejected the appeal. Hence this O.A. praying for as under:-

> ***"(a) for quashing of the impugned penalty order dated 23.11.2005 (Annexure No. A-1) passed by SSPOs City Division Kanpur as well as appellate order dated 29.6.2007 rejecting the appeal of applicant (Annexure No.-2) and to grant all consequential benefits of the restoration of pay scale.***
>
> ***(b) for a direction to the respondents to regularize the period of suspension and to restore the pay scale of Rs. 3050-75-80-4590 at the stage of Rs. 3075/- as on 23.11.2005 and grant all increments to the applicant from the date of punishment i.e. from 23.11.2005 in the pay scale of Rs. 3050-75-80-4590, as if no penalty was awarded to the applicant and pay him entire arrears of salary including the period of suspension along with the interest on market rate for the intervening period.***

8. Respondents have contested the O.A. and filed their counter, while the applicant had filed his rejoinder.

9. Counsel for the applicant had stated that when the individual was not a government servant during a particular period, there being no master and servant relationship, there is no need to inform the authorities on his resumption of duties about his having been in jail during the period he was out of service. He had relied upon the following decisions to support his case:-

(a) 2008 (1) AISLJ 536 – Hitender Singh vs Union of India & Ors

(b) 2005 (2) UPLBEC 1628 – Secy. Dept. of Home Secy. A.P. vs B. Chinnam

10. Counsel for the respondent submitted that the applicant cannot be said to have severed his relationship of Master and Servant during the period he was out of service, as the period of his suspension and dismissal had been regularized. And, the above decisions do not apply to the facts of the case.

11. Arguments were heard and documents perused. When the applicant was initially dismissed from service and then he had moved an appeal, followed by revision petition, he could do so only in his capacity as an ex government servant and when he was reinstated, and his period of absence regularized, he gains back the status as a government employee even during the period he was out of service. Thus, once the period of absence has been admittedly regularized save the exact period he was in jail. As such, there was every obligation to inform the department in terms of the Ministry of Home Affairs orders dated 25-02-1955 and 23-04-1955.

12. In so far as the decision of the Apex court in chinnam is concerned, the relevant portion relied upon by the applicant is as under:-

"8. In order to appreciate the rival submissions it is necessary to take note of column 12 of the attestation form and column 3 of the declaration. The relevant portions are quoted below:

> ***"Column 12.—Have you ever been convicted by a court of law or detained under any State/Central preventive detention laws for any offence whether such conviction sustained in court of appeal or set aside by the appellate court if appealed against."***
>
> ***"Column 3.—I am fully aware that furnishing of false information or suppression of any actual information in the attestation form would be a 750disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government."***
>
> ***9. A bare perusal of the extracted portions shows that the candidate is required to indicate as to whether he has ever been convicted by a court of law or detained under any State/Central preventive detention laws for any offences whether such conviction is sustained or set aside by the appellate court, if appealed against. The candidate is not required to indicate as to whether he had been arrested in any case or as to whether any case was pending. Conviction by a court or detention under any State/Central preventive detention laws is different from arrest in any case or pendency of a case. By answering that the respondent had not been convicted or detained under preventive detention laws it cannot be said that he had suppressed any material fact or had furnished any false information or suppressed any information in the attestation form to incur disqualification. The State Government and the Tribunal appeared to have proceeded on the basis that the respondent ought to have indicated the fact of arrest or pendency of the case, though column 12 of the attestation form did not require such information being furnished. The learned counsel for the appellants submitted that such a requirement has to be read into an attestation form. We find no reason to accept such contention. There was no specific requirement to mention as to whether any case is pending or whether the applicant had been arrested. In view of the specific language so far as column 12 is concerned the respondent cannot be found guilty of any suppression."***

13. The above decision does not assist the applicant inasmuch as there it was before joining the service the individual has to fill in the attestation form and the individual in that case gave the exact information, while the department expected more than what was required to be given. In the instant case, the 1955 Rules provide specifically as under:-

> ***"(2) Intimation about detention.-*** *It shall be the duty of a Government servant who may be arrested for any reason to intimate the fact of his arrest and the circumstances connected therewith to his official superior promptly even though he might have subsequently been released on bail. Failure on the part of any Government servant to so inform his official superior will be regarded as suppression of material information an will render him liable to disciplinary action on this ground alone, apart from the action that may be called for on the outcome of the Police case against him."*

14. Taking into account the conspectus of the entire case, we do not find any material irregularity I the conducting of the inquiry or the decision arrived at. The quantum of penalty is also commensurate with the gravity of misconduct.

15. In view of the above, the OA is devoid of merits and is dismissed.

Member (A) **Member (J)**

/pc/